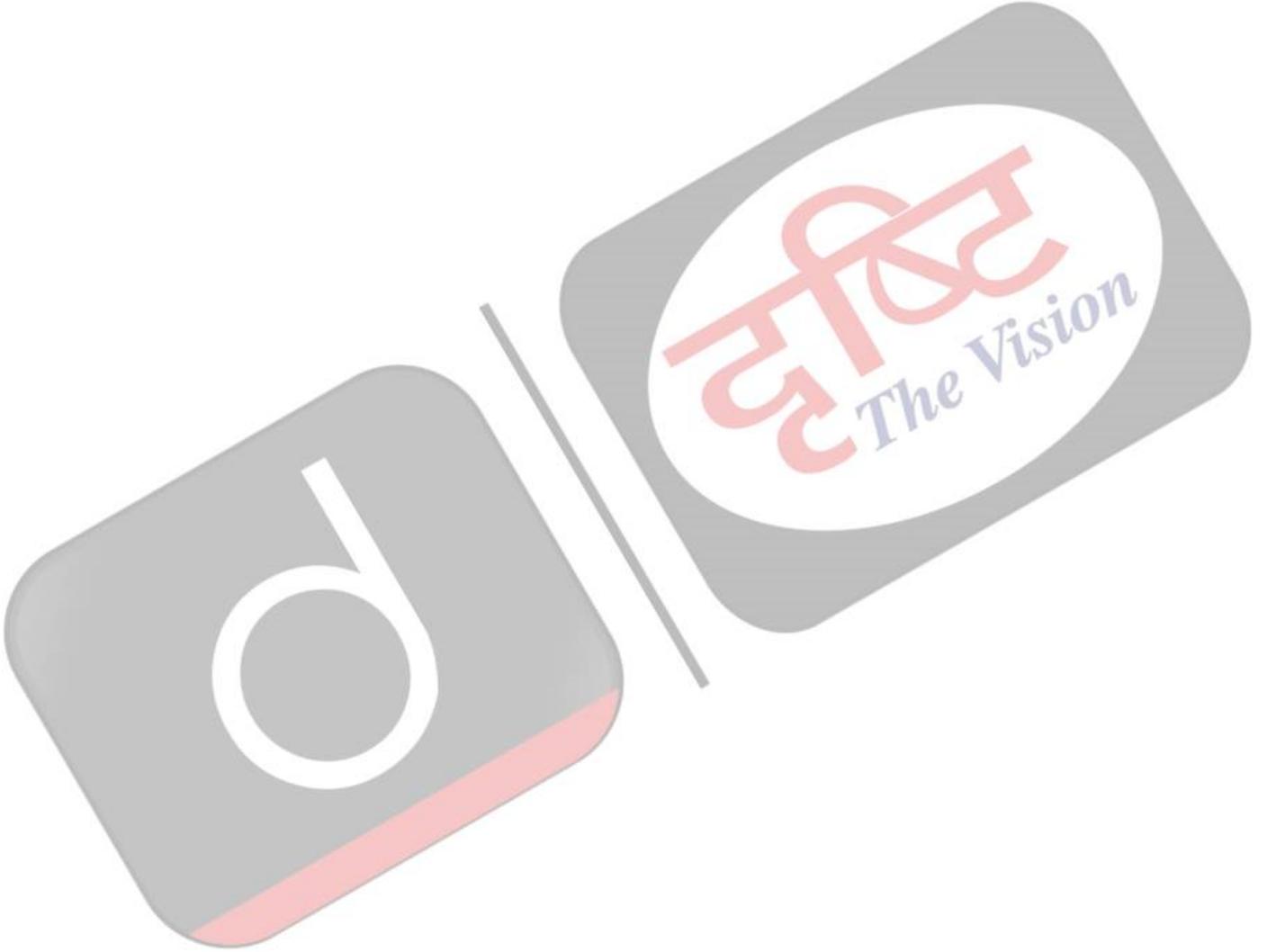


◦ साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कियद्यपि प्राकृतिक न्याय का सदिधांत महत्त्वपूर्ण है, फरि भी असाधारण परस्थितियों में ECI त्वरति और व्यावहारिक नरिणय ले सकता है।

- पूर्ववर्ती मतदाता सूची पुनरीक्षण: देश के वभिन्न भागों में वर्ष 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में वशिष संक्षपित पुनरीक्षण (SIR) आयोजति कयि गए थे। बहिर में अंतमि SIR वर्ष 2003 में आयोजति कयि गया था।

नोट: अनुच्छेद 327 संसद को वधिनमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है।

- **अनुच्छेद 328** राज्य की वधिनमंडल को उसके अपने चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है।





भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI)



ECI

- ◊ एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- ◊ लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- ◊ स्थापना- 25 जनवरी 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- ◊ 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं
- ◊ कार्यकाल- 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- ◊ सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र।
- ◊ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- ◊ चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- ◊ मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना
- ◊ चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- ◊ राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- ◊ राजनीतिक दलों के लिये आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) जारी करना
- ◊ सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना

चुनौतियाँ

- ◊ मुख्य चुनाव आयुक्त का छोटा कार्यकाल
- ◊ नियुक्तियों में कार्यकारी प्रभाव
- ◊ वित्त के लिये केंद्र पर निर्भरता
- ◊ स्वतंत्र स्टाफ की कमी



मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की आवश्यकता क्यों होती है?

- **तुरतिरहित और अद्यतन मतदाता सूची:** SIR का उद्देश्य अपात्र मतदाताओं को हटाना, नव पात्र या पूर्व में छूटे हुए मतदाताओं को जोड़ना और मतदाता सूची में तुरतियों को सुधारना होता है, ताकि सूची सटीक हो और धोखाधड़ी को रोका जा सके।
 - SIR प्रवासियों तथा स्थानांतरित जनसंख्या के लिये पुनः पंजीकरण को सरल बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची संशोधित नरिवाचन क्षेत्र की सीमाओं के अनुसार अद्यतन रहे।
- **लोकतांत्रिक वैधता की रक्षा:** SIR "वन परसन, वन वोट अर्थात् एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत को सशक्त करता है। यह फरजी और दोहराए गए मतदाताओं को हटाकर लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जाँच की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
- **मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहन:** SIR जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है और डोर-टू-डोर सर्वेक्षण तथा ऑनलाइन पंजीकरण तकियाओं के माध्यम से मतदाता पंजीकरण को सुलभ बनाता है — विशेष रूप से वंचित वर्गों को लाभ पहुँचाता है।
- **प्रोद्योगिकी और नीतित सुधारों को अपनाना:** SIR, मतदाता सूचियों के डिजिटल एकीकरण को प्रोत्साहित करता है और प्रवासी मतदाताओं के लिये रमित वोटिंग जैसी नीतित पहलों को लागू करने में सहायक होता है, जिससे सुलभता तथा दक्षता में सुधार होता है।
 - उदाहरण के लिये, बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने E-SECBHR ऐप के माध्यम से नगरपालिका चुनावों में मोबाइल ई-वोटिंग की पायलट परियोजना शुरू की। इसमें ब्लॉकचेन, फेशियल रकिगनशिन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग और वोटर आईडी सत्यापन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया।

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- **व्यापक मताधिकार वंचन का जोखिम:** आधार, राशन कार्ड या यहाँ तक कि मतदाता पहचान पत्र जैसे व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाले पहचान पत्रों को अस्वीकार करना, वंचित वर्गों पर अनुपातहीन रूप से प्रभाव डाल सकता है।
 - परंपरागत रूप से, मतदाता सूची में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को उनके सामान्य नविस स्थान के आधार पर शामिल किया जाता है, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया में उनके जन्म स्थान को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
- **प्रवासी शर्मकों पर प्रभाव:** प्रवासी शर्मकों, छात्रों और अस्थायी शर्मकों के बार-बार स्थान परिवर्तन के कारण नविस का प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है, जिससे उनकी मतदाता सूची से बहिष्करण का जोखिम बढ़ जाता है।
- **नागरिकों के गुप्त राष्ट्रीय रजिस्टर का संदेह:** जन्म प्रमाण पत्र या वंशानुगत दस्तावेजों की मांग को परोक्ष रूप से नागरिकता परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हाशिये पर और अल्पसंख्यक समुदायों के व्यवस्थित बहिष्करण की आशंका बढ़ जाती है।
 - यह आशंका जताई जा रही है कि SIR को पक्षपातपूर्ण ढंग से लागू किया जा सकता है, जिससे चुनावी अखंडता और समावेशी प्रतनिधित्व कमजोर हो सकता है।
- **जन परामर्श की कमी:** शीर्ष स्तर पर कार्यान्वयन और अत्यधिक दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के कारण सार्वभौमिक मताधिकार को नुकसान पहुँचाने का खतरा है, विशेष रूप से अशिक्षित और नरिशरति लोगों के लिये।

SIR प्रक्रिया की अखंडता और सटीकता को किस प्रकार मज़बूत किया जा सकता है?

- **समावेशी दस्तावेजीकरण नीतियाँ:** हालाँकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फरि भी यह वंचित समुदायों के लिये सबसे सुलभ पहचान पत्र है। इसलिये इसे नविस प्रमाणन के लिये स्वीकार किया जाना चाहिये तथा इसे पूर्ववर्ती अभिलेखों (legacy data) से क्रॉस-वेरफिकेशन द्वारा पूरक किया जाना चाहिये।
- **सुदृढ़ सत्यापन और डेटा सटीकता:** तुरतिरहित और पारदर्शी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपायों के साथ आधार-वोटर आईडी लकिगि, BLO द्वारा घर-घर सत्यापन और राज्य नरिवाचन आयोग जैसे चुनावी प्राधिकरणों द्वारा नियमित ऑडिट किया जाना चाहिये।
- **राजनीतिक और कानूनी सहमति:** चुनाव आयोग (ECI) को सभी हतिधारकों, जिसमें नागरिक समाज भी शामिल हो, से परामर्श करना चाहिये तथा SIR से जुड़े नियमों और अंतमि तथियों को स्पष्ट करने के लिये जन-जागरूकता अभियान चलाने चाहिये।
 - इसके अतिरिक्त, विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक नगिरानी और नरिवाचन नामांकन अधिकारियों (EROs) के लिये स्पष्ट दिशा-नरिदेश अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखा जा सके तथा मनमाने ढंग से मतदाताओं के बहिष्करण को रोका जा सके।
- **प्रोद्योगिकी-आधारित सुरक्षा उपाय:** AI-सक्ष्म वसिगत पहचान (Anomaly Detection) के माध्यम से संदेहास्पद वलियोपन/जोड़ (जैसे किसी एक क्षेत्र से एक साथ कई नाम हटना) की पहचान की जाए। ब्लॉकचेन-आधारित मतदाता लॉग लागू किए जाएँ और वास्तविक समय ट्रैकिंग डैशबोर्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छेड़छाड़ को रोका जा सके।
- **समावेशिता के उपाय:** वंचित समूहों (जैसे वकिलांग, आदवासी समुदाय) के लिये विशेष शरिरी का आयोजन किया जाए। बहुभाषी हेल्पलाइन शुरू की जाए और पुनरीक्षण के बाद नमूना सर्वेक्षण (sample surveys) कराए जाएँ, ताकि सटीक नामांकन सुनिश्चित किया जा सके और बहिष्करण को न्यूनतम किया जा सके।

